

## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है जो सिविल मंत्रालयों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुए। इसमें 12 अध्याय शामिल हैं। अध्याय I एक संक्षिप्त प्रस्तावना प्रदान करता है जबकि अध्याय II से XI विस्तृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां प्रस्तुत करते हैं। अध्याय XII मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई टिप्पणियों की एक सारांशीकृत स्थिति प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुल महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

### संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

#### डाक विभाग

#### डाक घरों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगस) वेतनों का संवितरण

संचालन में 4.90 करोड़ नरेगस खातों सहित, डाक विभाग नरेगस के अंतर्गत वेतनों के संवितरण हेतु बड़ा नेटवर्क प्रदान करता है। ₹ 4284 करोड़ की पर्याप्त राशि मार्च 2011 को कर्मचारियों के खातों में पड़ी थी। डाकघरों में प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन सहित दोनों मुख्यालय तथा परिमण्डल स्तरों में कमजोर मानीटरिंग क्रियाविधि का परिणाम मुख्य डाक घर में राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले एक बार जमा में 31 मार्च 2011 को ₹ 1920 लाख की सीमा तक की कमी में हुआ। नरेगस खातों के संचालन में वेतन के संवितरण में विलम्ब, सत्यापन के बिना खाते खोले जाना, खाता बहियों में अपूर्ण डाटा प्रविष्टियाँ, डाटा मिलान में गलतियाँ, ब्याज का न डाला जाना तथा अशिक्षित वेतन कमाने वालों के बायें हाथ के अंगूठे के निशानों के अनुप्रमाणन के बिना वेतन का संवितरण किया जाना जैसी अनियमिततायें भी पाई गई थीं।

#### पैराग्राफ 2.2

#### नकद प्रमाणपत्रों, टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री का भण्डारण

डाक विभाग नकद प्रमाणपत्रों, टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री को नियत करने तथा पूर्वानुमान लगाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने में विफल रहा। इसके साथ कमजोर आंतरिक नियंत्रण का परिणाम ₹ 3840.66 करोड़ के अंकित मूल्य के नकद प्रमाणपत्रों के अधिक भण्डारण तथा 31 मार्च 2011 को ₹ 498.52 करोड़ के अंकित मूल्य वाली टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री के अधिक भण्डारण में हुआ जिसने इस प्रकार इन मूल्यवान वस्तुओं को दुरुपयोग/चोरी तथा हानि के जोखिम में डाला।

#### पैराग्राफ 2.3

## ब्याज का अनियमित भुगतान

छः परिमण्डलों में डाकघरों ने सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (पी.पी.एफ.) से संबंधित प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन नहीं किया परिणामस्वरूप अभिदाताओं को ₹ 2.26 करोड़ के ब्याज का अनियमित भुगतान हुआ।

**पैराग्राफ 2.4**

## राजस्व टिकटों के क्रय पर कमीशन की कम कटौती

राज्य सरकार से राजस्व टिकटों के क्रय पर अग्रिम में कमीशन में कटौती करने पर मुख्य महाडाकपाल दिल्ली की विफलता से ₹ 98.36 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

**पैराग्राफ 2.5**

## डाक परिसर के निर्माण में विलम्ब के कारण निष्फल व्यय

1990 में प्राप्त किये प्लॉट पर डाक परिसर का निर्माण करने में डाक विभाग विफल रहा। इसका परिणाम ₹ 64.62 लाख के निष्फल व्यय में हुआ।

**पैराग्राफ 2.6**

## दूर संचार विभाग

### लेखापरीक्षा के बताये जाने पर अधिक सब्सिडी की वसूली

पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश (पूर्व) परिमंडलों द्वारा रूल कम्प्युनिटी फोन (आर.सी.पी.) के लिये सेवा सम्भरकों को ₹ 2.17 करोड़ की सब्सिडी का गलत भुगतान किया था जिसमें से ₹ 1.62 करोड़ लेखापरीक्षा के बताये जाने पर वसूल किये गये थे।

**पैराग्राफ 2.8**

## विदेश मंत्रालय

### वाणिज्यदूत स्कंध का निष्पादन

कुछ मिशन तथा केन्द्र मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वीजा तथा अन्य वाणिज्यदूत सेवाओं हेतु शुल्कों का उद्ग्रहण नहीं कर रहे थे जिसका परिणाम ₹ 37.26 करोड़ के कम उद्ग्रहण में हुआ। मिशनों तथा केन्द्रों द्वारा भारतीय समुदाय विकास निधि योजना के कार्यान्वयन में विलम्बों का परिणाम ₹ 21.55 करोड़ के शुल्कों के गैर-

उद्ग्रहण में हुआ। सरकारी खाते में वाणिज्यदूत प्राप्तियों के धन प्रेषणों में पर्याप्त विलम्ब थे। विदेश में मिशन ने निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में वीजा सेवाओं की आउटसोर्सिंग की थी जिसका परिणाम वित्तीय अनुपयुक्तता तथा सेवा प्रदाताओं के चयन में पारदर्शिता की कमी में हुआ।

### पैराग्राफ 3.1

**निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता अधिक भुगतानों का कारण बनी**

निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं का पालन करने में विदेश में मिशनों/केन्द्रों की विफलता 263 मामलों में 56 मिशनों द्वारा कुल ₹ 91.96 लाख की राशि तक के वेतन एवं भत्तों तथा अन्य विविध भुगतानों के अधिक भुगतान का कारण बनी। इन्हें 2009-11 के दौरान लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूला गया था।

### पैराग्राफ 3.1.1

**अनुबंध देने में समुचित अध्यवसाय का अभाव**

इंडोनेशिया में एक सू.प्रौ. प्रयोगशाला के संस्थापन हेतु बोलियों के मूल्यांकन में समुचित विवेकपूर्णता का अभाव, अनुचित वार्षिक अनुरक्षण प्रभार एवं अतिरिक्त मूल्य वर्द्धित कर में छूट, के बाबत 51.67 लाख के अतिरिक्त राशि पर अनुबंध को सौंपे जाने का कारण बना। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, मिशन ने ₹ 30.56 लाख की वसूली की तथा ₹ 21.11 लाख के भुगतान को रोका।

### पैराग्राफ 3.1.1

**गृह मंत्रालय**

**भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल**

**संस्वीकृतियों का विभाजन**

महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने जून 2010 तथा मार्च 2011 के बीच ₹ 4.72 करोड़ की कुल मूल्य की 19 विभाजित संस्वीकृतियाँ प्रदान की। प्रत्येक संस्वीकृति, मंत्रालय को मामला प्रेषित करने की आवश्यकता से बचने के उद्देश्य से, ₹ 25 लाख की वित्तीय शक्ति के भीतर सीमित की गई थी।

### पैराग्राफ 4.1

## आसूचना ब्यूरो

अनुपयुक्त प्रापण योजना के कारण परियोजना के निष्पादन में विलम्ब तथा उपकरणों का निष्क्रिय पड़े रहना

आसूचना ब्यूरो द्वारा इनक्रिप्टर्स का प्रापण करने से पूर्व इंटरनेट नेटवर्क के संस्थापन हेतु विभिन्न संबंधित कार्यों को समक्रमिक करने की विफलता दो वर्षों की अवधि तक ₹ 2.89 करोड़ के व्यर्थ पड़े रहने का कारण बनी।

### पैराग्राफ 4.2

स्टाफ मकानों के निर्माण में असाधारण विलम्ब

सहायक आसूचना ब्यूरो, लखनऊ द्वारा स्टाफ आवासों के निर्माण में असामान्य विलम्ब से लागत में ₹ 2.17 करोड़ की वृद्धि हुई। इसका परिणाम अपने स्टाफ सदस्यों को आवास किराया भत्ता के भुगतान के प्रति ₹ 86.59 लाख के परिहार्य व्यय में भी हुआ।

### पैराग्राफ 4.3

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्च शिक्षा विभाग

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर संशोधक कार्रवाई

मंत्रालय वर्तमान नियमों के अनुवर्तन में विफल रहा और आई.आई.टी. मद्रास के रिसर्च पार्क को प्रयोज्य ब्याज दर 11.5 प्रतिशत के स्थान पर तीन प्रतिशत पर ₹ 100 करोड़ का ऋण दिया। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर मंत्रालय ने ब्याज दर को परिवर्तित करने की संशोधक कार्रवाई की जिससे ₹ 46.75 करोड़ का घाटा होने से रोका गया।

### पैराग्राफ 5.1

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

किराया बकायों की गैर-वसूली

फिल्म प्रभाग, मुंबई बंद तथा समाप्त प्रदर्शकों से कुल ₹ 60.73 लाख के किराया प्रभागों की वसूली करने में विफल रहा।

### पैराग्राफ 6.1

## संघ शासित क्षेत्र

### अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

#### जहाजरानी सेवाएं निदेशालय

#### कार्य-मुक्त किए गए एक जलयान के विक्रय में विलम्ब के कारण हानि

एक अतिजीवित जलयान के उचित आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए समय से कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 6.29 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

#### पैराग्राफ 8.1

#### एक अतिजीवित पोत पर परिहार्य व्यय

अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा निष्प्रभावी सहयोग एवं अनुवर्तन के कारण एक अतिजीवित पोत की वापसी में विलम्ब हुआ तथा परिणामतः ₹ 3.69 करोड़ के परिहार्य व्यय का कारण बना।

#### पैराग्राफ 8.2

## लक्षद्वीप प्रशासन

### एक्स-रे बैगेज जाँच प्रणाली का प्रापण

आवश्यक अवसंरचना के सृजन सहित दो एक्स-रे बैगेज जाँच प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापन तथा चालू करने को समकालिक बनाने में संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन की विफलता के परिणामस्वरूप प्रणालियों की खरीद पर ₹ 61 लाख व्यय करने के बावजूद यात्रियों के बचाव एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

#### पैराग्राफ 8.3

## महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

### लेखापरीक्षा दृष्टांत पर अनुदान की अधिक निर्मुक्ति की वसूली

राज्य सरकारों को अनुदान जारी करते समय उचित तत्परता का प्रयोग करने में मंत्रालय की विफलता का परिणाम ₹ 3.45 करोड़ की अधिक निर्मुक्ति में हुआ इसे बाद में लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूला गया था।

#### पैराग्राफ 9.1

### एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंश की अनियमित निर्मुक्ति

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अम्बाला एवं हिसार में दो अवलोकन गृहों के निर्माण हेतु दो केन्द्रीय योजनाओं अर्थात् फरवरी 2008 में किशोर न्याय कार्यक्रम तथा दिसम्बर 2010 में एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अंतर्गत कुल ₹ 1.08 करोड़ के अनुदान दो बार जारी किए।

**पैराग्राफ 9.2**

### परमाणु ऊर्जा विभाग

#### ₹ 3.32 करोड़ का परिहार्य व्यय

क्रय प्रक्रिया का अनुपालन करने में परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन क्रय एवं भण्डारण निदेशालय की विफलता तथा वैधता अवधि के भीतर क्रय प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में परिणामी विलम्ब का परिणाम ₹ 3.32 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

**पैराग्राफ 10.1**

### अंतरिक्ष विभाग

#### माँग प्रभारों का परिहार्य भुगतान

सही प्रकार से अपनी विद्युत खपत आवश्यकताओं का निर्धारण करने में इसरो उपग्रह केन्द्र तथा इसरो टेलीमेटरी, ट्रैकिंग एवं कमांड नेटवर्क की विफलता के साथ अनुबंधित माँग को कम करने हेतु कार्यवाही करने में विलम्ब का परिणाम विद्युत की खपत हेतु ₹ 3.72 करोड़ के परिहार्य भुगतान में हुआ।

**पैराग्राफ 11.1**